year 70-71, an area of 8.00 lakh hects, is likely to be surveyed at a total cost of Rs. 7 50 lakhs.

(b) A detailed soil survey of 2.75 lakh hectares is being undertaken in the catchments of 13 continuing and 8 newly selected river valley projects during the year 1970-71.

(c) and (d). The Centrally Sponsored Programme of soil and water conservation in the catchments of river valley projects has been intensified during the Fourth Five Year Plan. The work is being concentrated in the priority watersheds identified by aerial photo interpretation and detailed soil survey. An outlay of Rs 2700 lakhs has been approved under the Centally Sponsored Programme during the Fourth Plan.

Film on Netaji Postponed

2452. SHRI J. AHMED : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) Whether Government have postponed the work on a feature film on Netaji Subhash Chandra Bose in view of the enquiry pending; and

(b) if so, whether the work will be resumed as soon as the enquiry is over ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) No feature film is being produced by the Government of India on Netaji. Two feature films on Netaji produced by private parties have already been released. A private producer has been commissioned by the Films Division to produce a documentary film on Netaji.

(b) The question does not arise.

Strike by Road Corporation Workers in West Bengal

2453. SHRI B. K. MODAK :
SHRI P. RAMAMURTI :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether a strike was observed by theWorkers belonging to the Road Corporation of India on the 22nd October, in West Bengal and Bihar in protest agnaist the police firings, lathi-charges and the use of the tear-gas on the workers of Sankrail Food Depot, Howrah;

(b) if so, whether Government propose to institute an impartial inquiry into the Sankrail incident; and

(c) if so, the details of the steps taken in this regard ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA) : (a) to (c). The information is being collected and would be laid on the Table of the House after it is received.

राजस्थान में खादर को कृषि योग्य बनाया जाना

2454. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में खादर को कृषि योग्य बनाने पर कितना व्यय किया गया;

(ख) इस योजना पर उक्त अवधि में कोटा राजस्थान में कितना व्यय किया गया;

(ग) इस योजना के भावी कार्यक्रमों के लिए कितना धन नियत किया गया है तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया; और

(ङ) कृषि योग्य बनाई गई भूमि का किस उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा 1967-68 से 1969-70 तक के पिछले 3 सालों में

राज्य योजना स्कीमों के अधीन 5.29 लाख रुपये और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन 2·38 लाख रुपये की रकम व्यय की है।

(ख) कोटा में बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एक मार्गदर्शी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का काम 1969-70 में आरम्भ किया गया था और उस वर्ष 2·38 लाख रुपये की रकम व्यय की गई थी।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन 50 लाख रुपये की राशि और राज्य योजना में 16 लाख रुपये की राशि निर्धारित की है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में 2500 एकड़ भूमि को कृषि अधीन और 2500 एकड़ को वनारोपण के अधीन लाने की व्यवस्था है। इस के अतिरिक्त चौथी योजना की अवधि में 5000 एकड़ में राज्य योजना स्कीम के अधीन वनारोपण करने की व्यवस्था है।

(घ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन 200 एकड़ भूमि कृषि योग्य बना कर कृषि अधीन लाई गई है और 150 एकड़ वनारोपण के अधीन लाई गई है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना स्कीम के अधीन 7687 एकड़ भूमि में वनारोपण किया गया है।

(ङ) यह स्कीम चौथी योजना के आरम्भ की गई है ताकि बड़े आकार की बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के तकनीकों और आर्थिक सम्भाव्यताओं को निर्धारित किया जाये और उन्हें वनारोपण और काश्त धन्धों के लिये प्रयोग में लाया जा सके।

शिमला में हुआ अखिल भारतीय संवाददाता सम्मेलन

2455. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में शिमला में हुई अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन में पास किये गये संकल्प की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ. कु. गुजराल) : (क) अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक के महासचिव द्वारा भेजे गये सम्मेलन के शिमला अधिवेशन में पारित प्रस्ताव सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(ख) समाचार पत्रों को विज्ञापन देने सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति सदन की मेज पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रख दी गयी : देखिये संख्या** LT–4399/70]

अखबारी कागज आवंटन सम्बन्धी वार्षिक नीति आयातित तथा देशी स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाले अखबारी कागज तथा छोटे और मंझोले समाचार पत्रों के विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है।

समाचार पत्रों के पंजीकरण तथा अखबारी कागज के आवंटन की वर्तमान प्रक्रिया सरल है तथा प्रार्थना पत्रों पर अविलम्ब कार्रवाई करने के लिए समस्त अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता के अनुरूप है।

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत 2,000 प्रतियों तक की खपत का दावा करने वाले प्रकाशकों को आडिटर का प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। लघु समाचार पत्र सम्बन्धी जांच समिति को इस संख्या को बढ़ा कर 5,000 या 10,000 तक करने के लिये अभ्यावेदन दिए गए थे। समिति ने इस सुझाव का समर्थन नहीं किया और सरकार ने उसकी सिफारिश स्वीकार कर ली।